दिव्यांगजनों ने शिक्षा, विज्ञान, संगीत और तकनीक समेत हर क्षेत्र में प्रतिभा साबित की : मुख्यमंत्री

राजस्थान को दिव्यांगों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज खेल जगत से लेकर शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला और तकनीक सहित हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा साबित की है। इन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हम अपने आस-पास रह रहे दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचानते हुए इनका पूरा सहयोग करें जिससे इनकी विशेष योग्यता का लाभ समाज को मिल सके तथा एक समावेशी समाज का निर्माण हो। हमारा संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बने। भजनलाल शर्मा बुधवार को हरीश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) में अन्तरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को अन्तरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित समारोह में दिव्यांगों से बातचीत की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष योग्यजन अपने भीतर विशेष योग्यता रखते हैं। ये अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, दृढ़संकल्प और मेहनत से हर सीमा को पार करने का साहस रखते हैं।

इनमें वह हुनर और जज्बा होता है जो किसी सामान्य व्यक्ति में मुश्किल से मिलता है। उन्होंने कहा कि पैरालम्पिक में हमारे खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश को जो सम्मान दिलाया है, वह उनकी ऊर्जा और क्षमता का प्रमाण है। इनकी सफलता की कहानियां हम सभी को प्रेरित करती हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा देश में एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक चुनौतियां उसकी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए बाधा न बन सकें। केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिनियम के माध्यम से विकलांगता की परिभाषा को सात श्रेणियों से बढ़ाकर 21 श्रेणियों तक किया है। इसमें एसिड अटैक सरवाइवर को भी शामिल किया गया है। यह कानून दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने एवं सामाजिक धारणाओं को बदलने में मददगार साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में विशेष योग्यजन के लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, स्मार्टफोन, व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, पेंशन इत्यादि से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

हमने विद्यार्थियों एवं स्वरोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को गत वर्ष 2 हजार स्कूटी वितरित की हैं तथा इस वर्ष दिव्यांगजनों को ढाई हजार स्कूटी वितरित की जा रही है। साथ ही, दिव्यांगजनों के लिए प्रदेशभर में विभिन्न क्लस्टर बनाए गए है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल दिव्यांगजनों को 15 हजार अंग उपकरण वितरित किए थे और इस वर्ष 1 लाख अंग वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हील चेयर का वितरण किया जा रहा है। साथ ही, विशेष योग्यजनों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का इस वर्ष से मैस भत्ता 2500 से बढ़ाकर 3250 रुपये प्रति आवासीय कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण करवाकर यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जारी करने में राजस्थान देशभर में अग्रणी राज्यों में शामिल है।

समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया। साथ ही, उन्होंने विशेष योग्यजनों को स्मार्टफोन, श्रवण यंत्र एवं स्मार्ट केन भी वितरित किए। इससे पूर्व उन्होंने दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों को स्कूटी वितरण एवं अंग उपकरण भी वितरित किए।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता अपर्णा अरोड़ा, विशेष योग्यजन निदेशालय आयुक्त इकबाल खान सहित अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विशेष योग्यजन उपस्थित रहे।

इथेनॉल मिश्रण से किसान को लाभ और प्रदूषण में कमी : मदन राठौड़

- सांसद मदन राठौड ने कहा कि ''नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार गन्ना आधारित इथेनॉल से 65 प्रतिशत व मक्का आधारित इथेनॉल से 50 प्रतिशत तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है।''
- 'वर्ष 2014-15 से अक्टूबर 2025 तक किसानों को एक लाख 36 हजार 300 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान किया'

जयपुर। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सदन में देश की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर सवाल लगाया। राठौड़ ने बताया कि इथेनॉल नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसने भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अप्रत्याशित गति से आगे बढ़ाया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सदन में बताया कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। वर्ष 2013-14 के केवल 38 करोड़ लीटर की तुलना में वर्ष 2024-25 में इथेनॉल मिश्रण क्षमता बढ़कर 1000 करोड़ लीटर से अधिक हो चुकी है। अक्टूबर 2025 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर है।

मदन राठौड़ ने कहा कि यह केवल उत्पादन वृद्धि नहीं है, बल्कि सरकार ने फीडस्टॉक विस्तार, जीएसटी में 5 प्रतिशत कमी और चीनी मिलों व डिस्टिलरियों के आधुनिकीकरण जैसे निर्णायक कदम उठाकर इथेनॉल उपलब्धता सुनिश्चित की है। सरकार द्वारा 233 दीर्घकालिक ऑफटेक समझौते तथा सहकारी चीनी मिलों के लिए विशेष वित्त सहायता से देश की डिस्टिलेशन क्षमता बढ़कर 1950 करोड़ लीटर हो गई है। साथ ही भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से 52 लाख मीट्रिक टन अधिशेष चावल और चीनी का डायवर्जन किया गया, जिससे किसानों को स्थायी बाजार मिला और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सांसद मदन राठौड ने कहा कि नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार गन्ना आधारित इथेनॉल से 65 प्रतिशत और मक्का आधारित इथेनॉल से 50 प्रतिशत तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। यह शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने में बड़ा परिवर्तन साबित हो रहा है। सरकार द्वारा कराए गए परीक्षणों ने यह भी सिद्ध किया कि ई-20 ईंधन से वाहनों के इंजन प्रदर्शन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अधिक ऑक्टेन के कारण पिकअप और ड्राइविंग स्मूथनेस बढ़ती है। राठौड़ ने बताया कि वर्ष 2014-15 से अक्टूबर 2025 तक किसानों को 1 लाख 36 हजार 300 करोड़ का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है। साथ ही देश ने 1.55 लाख करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत, 790 लाख एमटी सीओ2 उत्सर्जन में कमी और 260 लाख एमटी कच्चे तेल के आयात का प्रतिस्थापन हासिल किया है।

विधायक शोभारानी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधडी को लेकर धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह को राहत देते हुए भरतपुर की निचली अदालत की ओर से मामले में लिए गए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शोभारानी कुशवाह की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसे में भरतपुर के एसीजेएम कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2022 और महिला उत्पीडन कोर्ट के 12 मई, 2023 के प्रसंज्ञान आदेश को निरस्त किया जाता है।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र और अधिवक्ता जया मित्र ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एक महिला है और वह न तो कंपनी के प्रबंधन से जुडी है और ना ही उसके निदेशक मंडल की सदस्य है। वह कंपनी की केवल शेयर धारक है और अपनी के दैनिक कामकाज या निर्णय लेने में कोई भागीदारी भी नहीं रखती है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं है। इसके अलावा मामले में पुलिस ने न तो याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया और ना ही उसके खिलाफ कोई जांच लंबित है। इसके बावजूद निचली अदालत ने केवल कंपनी के शेयर धारक होने के आधार पर उसे अपराध में शामिल मानकर प्रसंज्ञान ले लिया। वहीं मामले के शिकायतकर्ताओं के साथ समझौता हो चुका है और प्रकरण पूरी तरह सिविल प्रकृति का है। ऐसे में उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधडी को लेकर भरतपुर के मथुरा गेट पुलिस थाने में शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 406 व 120 बी में मामला दर्ज किया। वहीं जांच के बाद पुलिस ने शोभारानी के पति बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ चालान पेश किया और करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी थी।

राजस्थान अब बनेगा पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल्स क्षेत्र में अग्रणी राज्य

रीको की पहल पर ''प्लग एंड प्ले'' तथा ''फैक्ट्री शेड्स'' बन रहे हैं उद्यिमयों की पसंद

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। पचपदरा (बालोतरा) स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के निकट विकसित किए जा रहे रीको के राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यिमयों की ओर से उत्साहजनक रूझान दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत राजस्थान पेट्रो जोन के प्रथम फेज में नियोजित भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है।

औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा में स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में रिफाइनरी के सह-उत्पाद आधारित उद्योगों हेतु प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत 16 निवेशकों को भूखण्ड आवंटित किए जा रहे हैं जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स से जुडे उद्योगों के प्रति निवेशकों की बढ़ती रूचि का संकेत है। रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पाद जैसे प्रोपलीन, बेंजीन, टोल्यून और ब्यूटाडाइन जैसे फीडस्टॉक का उपयोग आरपीजेड में लगने वाले उद्योगों में ही कच्चे माल के रूप में हो सकेगा एवं इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

- भजनलाल सरकार की रियायतों और नवाचारों से राजस्थान में उद्योग लगाना अब और भी आसान हुआ

आरपीजेड में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड्स

ऐसे उद्यमी जिनके पास पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल्स में टेक्निकल योग्यता तो है परंतु पूंजी की उपलब्धता नहीं है, उनके लिये रीको आरपीजेड में ही प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड भी बना रहा है। शेड्स का क्षेत्रफल 1600 से 2700 वर्गमीटर तक है। वर्तमान में रीको ऐसे करीब 8 प्लग एवं प्ले फैक्ट्री शेड्स का आरपीजेड में निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार, जो उद्यमी कम लागत पर अपनी औद्योगिक इकाई लगाना चाहते हैं, उनके लिये रीको द्वारा राज्य में प्रथम बार जयपुर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में ''रेडी-टू-मूव इन'' मॉड्यूल्स बनाये हैं। उद्यमी इन 'रेडी-टू-मूव इन' मॉड्यूल्स में अल्प समय में ही अपनी इकाई शुरू कर सकते हैं। ऐसी सुविधा को उद्यमी हाथों हाथ ले रहे हैं। रीको द्वारा प्रथम चरण में 7 उद्यिमयों को मॉड्यूल्स आवंटन के लिये ऑफर लेटर जारी कर दिये गये हैं। यहां गारमेंट एवं अपैरल क्षेत्र की इकाइयाँ स्थापित होंगी जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस कॉम्प्लेक्स में कई तरह की सुविधायें यथा प्रशासनिक कार्यालय, बैंक, प्रशिक्षण कक्ष, सभा कक्ष और कैंटीन भी उपलब्ध हैं। यहां गारमेंट एवं अपैरल उद्योग हेतु 1236 से 1566 वर्गफीट के बिल्टअप मॉड्यूल्स 1 से 7 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस फीस आधार पर दिए जा रहे हैं, जिससे उद्यमी उत्पादन गतिविधियां तुरंत ही शुरू कर सकते हैं।

राजस्थान को ''बाल विवाह मुक्त'' के लिए सरकार प्रतिबद्ध : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है।

दिया कुमारी बताया कि राज्य सरकार 2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अग्रसर है- जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के अधिकारों का संरक्षण, सुरक्षा तंत्रों को सुदृढ़ करना तथा बच्चों को सम्मान, अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनजागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 100 दिनों के विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगी। सम्पूर्ण कार्यक्रम का वेबकास्ट प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा।

बाल अधिकारिता आयुक्त आशीष मोदी ने बताया कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी, जैसे कि डीपीओ, सीएमपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हैल्पर और ओएससी, एचईडब्ल्यू, शक्ति सदन, सखी निवास, सीसीआई, सीडब्ल्यूसी और जेजेपी आदि के अधिकारी/कर्मचारी, प्रतिनिधियों, स्वास्थ्यकर्मियों, विधिक समुदाय, शैक्षिणक संस्थानों, समुदाय के नेताओं, सेवा प्रदाताओं और सिविल सोसायटी से इस कार्यक्रम में वर्चुअल उपस्थिति देने का अनुरोध किया गया है।

कलेक्ट्रेट में बम की सूचना से हडकंप मचा

जयपुर। बनीपार्क थाना इलाके में स्थित कलेक्ट्रेट में ई - मेल के जरिए बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया और कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ,एटीएस, बम डिस्पोजल टीम, सिविल डिफेंस और दमकल की टीमें ने मोर्चा संभाला और तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवा कर चप्पे-चप्पे की तलाशी लेते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया। करीब दो घंटे चली इस कार्रवाई में टीम को किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिसके बाद टीम ने राहत की सांस ली। पुलिस अधिकारियों ने यह ई-मेल फर्जी बताया।

एसआईपीएफ विभाग की व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पारदर्शी, सुगम एवं सुशासन के लक्ष्य को धरातल पर साकार करने के लिए उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी के निर्देश पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने कार्मिकों की सुविधा के लिए एक नया व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। विभाग के संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क एवं मुख्यालय) प्रहलाद कुमार मीना ने बताया कि 9462255117 नम्बर को सेव करने पर यह ऑटोमेटिक एसआईपीएफ डिपार्टमेंट के नाम से सेव हो जाएगा। इस चैटबॉट के माध्यम से कार्मिक को अपने खाता, लेजर और अन्य सम्बन्धित जानकारी सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी। व्हाट्सएप पर महत्वपूर्ण जानकारी, सभी संदेश एसआईपीएफ डिपार्टमेंट के नाम से दिखेंगे जिससे कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने में आसानी होगी कि वे अधिकारिक संदेश ही देख रहे है। मीना ने बताया कि विभाग की यह पहल डिजिटल सेवा को मजबूत करने और कार्मिक के समय व मेहनत बचाने के उद्देश्य से की गई है। इससे कार्मिकों की सुरक्षित, आसान और पारदर्शी तरीके से अपने वित्तीय विवरण तक पहुँच सुनिश्चित होगी। विभाग ने सभी कार्मिकों से अनुरोध किया है कि वे केवल अधिकारिक संदेशों पर भरोसा करें।

देवनानी और बोहरा ने किए खाटूश्यामजी के दर्शन

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जयपुर शहर के पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने बुधवार को खाटूश्याम पहुंचकर श्रद्धापूर्वक खाटू मंदिर में दर्शन किए। देवनानी ने प्रदेश की समृद्धि, जनकल्याण और सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि खाटूश्याम का आशीर्वाद सदैव समाज को सद्भाव, शक्ति और सकारात्मकता का संदेश देता है।

103 यूनिट रक्तदान

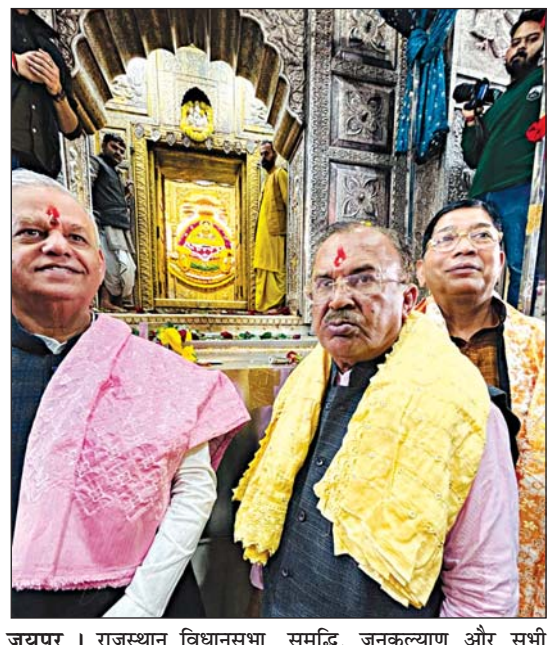

जयपुर। समाज सेवा के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में, एंकर प्रीति सक्सेना ने अपने जन्मदिवस पर जयपुर के राजापार्क, गली नंबर 3 स्थित राम मंदिर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया। जहां 103 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। 15 वर्षों से, प्रीति सक्सेना अपने जन्मदिवस को मानव सेवा के प्रति समर्पित करती आ रही हैं, और इस वर्ष भी उन्होंने इसी परंपरा का निर्वहन किया।

अज्ञात बदमाशों ने कब्र खोदकर हटाई पट्टियां

शास्त्री नगर के नाहरी का नाका कब्रिस्तान का मामला

- सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों में फैला आक्रोश
- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश के बाद कब्र में वापस मिट्टी डलवाई

जयपुर। शास्त्री नगर के नाहरी का नाका कब्रिस्तान में मंगलवार देर रात अज्ञात लोगों ने दो कब्र खोद दी। दोनों कब्रों से पत्थर की पट्टिकाएं हटाई हुई थी। सुबह फातिहा पढ़ने गए व्यक्ति ने अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। बड़ी संख्या पर स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। असामाजिक तत्वों की करतूत से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। जिन दो कब्रों को खोदा गया है उनमें दफन व्यक्तियों में एक की मौत तीन दिन पूर्व और एक की डेढ़ पहले हुई बताई जा रही है। श्मशान का प्रबंधन करने वाली कमेटी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। एडीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कब्र में वापस मिट्टी डलवाई। बाद में उन्होंने शास्त्री नगर पुलिस थाने में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की।

स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 6 माह पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था। तब विधायक अमीन कागजी ने दीवार ऊंची करवाने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने और दरवाजे पर ताला लगाने का आश्वासन दिया था। मगर केवल दीवार ऊंची करवाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। रात को कब्रिस्तान में अंधेरा रहता है उसी की आड़ में असामाजिक तत्व क्रबों से छेड़छाड़ करते है। कई साल पहले एक बच्चे की कब्र भी खोद डाली थी।

उस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चों के कब्रिस्तान की दीवार तो ऊंची करवा दी और दरवाजे पर ताला लगवा दिया। लेकिन मुख्य कब्रिस्तान 24 घंटे खुला रहता है। यहां कोई चौकीदार भी नहीं है।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN
RISING™ RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

प्रत्यक्ष आवंटन योजना - 2025
राइज़िंग राजस्थान में MoU करने वाले निवेशकों के लिए भूखण्ड के आरक्षित मूल्य पर
औद्योगिक भूखण्डों का डायरेक्ट अलॉटमेंट
सातवाँ चरण
ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांक 05.12.2025 (प्रातः 10:00 बजे) से 18.12.2025 (सायं 6 बजे) तक आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।
नियोजित लॉजिस्टिक भूखण्डों का आवंटन भी आरक्षित मूल्य पर | ई-लॉटरी 23 दिसम्बर, 2025
108 औद्योगिक क्षेत्र | 7 नए औद्योगिक क्षेत्र | 6,034 कुल औद्योगिक भूखण्ड | 5,263 अनारक्षित भूखण्ड | 40 लॉजिस्टिक भूखण्ड
नए औद्योगिक क्षेत्र
धुँवाला (भीलवाड़ा) | रुंध सौखरी (अलवर) | बरोली (धौलपुर) | पीपलूंद (भीलवाड़ा) | कीडीमाल (भीलवाड़ा) | सथाना - जनरल जोन (ब्यावर) | केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर)
विभिन्न श्रेणियों / वर्गों के लिए आरक्षित भूखंड
215 अनुसूचित जाति/जनजाति | 224 महिला वर्ग | 118 भूतपूर्व सैनिक | 146 बेंचमार्क दिव्यांगता | 68 सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक के आश्रित
आवंटन की प्रक्रिया
एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन
EMD - भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाइन जमा।
पात्रता - निवेशक जिन्होंने 19/11/2025 तक राइजिंग राजस्थान में राज्य सरकार के साथ एमओयू किये हैं वे सभी इस योजना में भूखण्ड के लिए पात्र हैं।
- भूखण्ड का आवंटन एमओयू धारक के नाम पर ही जारी किया जाएगा।
आवेदन हेतु स्कैन करें
भूखण्ड की राशि का भुगतान
*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
RIICO की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
इस योजना के तहत भूखण्ड देखने या आवेदन करने के लिए https://riico.rajasthan.gov.in पर दिए गए Direct Land Allotment लिंक पर क्लिक करें या riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/DirectLand पर विजिट करें।
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए
राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005
हैल्पलाइन नंबर : 0141 4593250, 4593237 | वाट्सएप : +91 90013 06515 | ई-मेल : riico@riico.co.in
riico.rajasthan.gov.in · riicogis.rajasthan.gov.in/riicogiscitizen
राज.संवाद/सी/25/15128